POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983)

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जुलाई, 2026

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से पोस्टकार्ड

जीवन और विरासत के बीच

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

13 मई 2026 को मैं जयपुर के इटरनल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था। मुझे गंभीर निमोनिया था और साथ ही उम्र से जुड़ी कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं, जिनमें मधुमेह (डायबिटीज) भी शामिल है। वहां के अनुभवी चिकित्सकों ने मेरी बड़ी देखभाल की। एक जून को मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और अब मैं घर पर हूं। मुझे दुरुस्त होने में लम्बा समय लगेगा।

मुझे खुशी है कि इसी दौरान डॉ. प्रतीक भारद्वाज ने मुझे वर्ष 2025 की गंगानगर के एक संपन्न किसान की धटना सुनाई जो गंभीर हालत में था और उसने भी जीवन के अंत की इच्छा जताई थी। तब उनके परिवार और डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी स्थिति में होता, तो क्या वह उसे हार मानने देते? किसान ने तुरंत जवाब दिया, 'नहीं'। बाद में उस किसान ने गंगानगर में अपने लिए सुविधाओं वाला एक आईसीयू कमरा बनवाया, किसान पूरी तरह स्वस्थ हुआ और फिर अपने खेतों में वापस लौट गया।

यह कहानी मेरे दिल को छू गई। डॉ. भारद्वाज ने मुझे भी यह विश्वास दिलाया कि मुझे भी दुरुस्त होने के उतार-चढ़ाव से गुजरना चाहिए और धीरे-धीरे अपने कामकाजी जीवन में लौटना चाहिए-शायद पहले से थोड़ी धीमी गति से, लेकिन अधिक स्पष्ट सोच और बेहतर दृष्टिकोण के साथ। इससे मेरी जीवटता जागृत हुई।

मैं, डॉ. भारद्वाज का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने अपनी समझदारी भरी बातों से मुझे जीवन जीने का नया उद्देश्य दिया। साथ ही, मैं अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, चाहे वे पास हों या दूर।

मैंने उनसे अपने जीवन के एक बड़े उद्देश्य के बारे में भी बात की-विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को उसकी पूरी प्रभावशीलता के साथ फिर से स्थापित करने का सपना। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा संगठन है जो नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा करता है।

बहुत पहले प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री प्रो. जगदीश भगवती ने कहा था, "जब प्रदीप बोलते हैं, तो दुनिया सुनती है।" आज शायद पहले से भी अधिक आवश्यकता है कि दुनिया उनकी बात सुने, क्योंकि भारत अब केवल "ना" कहने वाला देश नहीं, बल्कि शर्तों के साथ "हाँ" कहने वाला देश बनकर आगे बढ़ रहा है।

मेरी वेबसाइट पर भी उल्लेख है कि मुझे प्रो.भगवती से निरंतर प्रेरणा मिलती रही है। उन्होंने कभी मुझे "भारत की एक जीवित धरोहर और देश के लिए एक वरदान" कहा था।

कुछ लोग चुपचाप खो जाने के लिए नहीं बने होते- वे फिर उठ खड़े होते हैं और दुनिया को प्रेरित करते रहते हैं।

बैंक लॉकर के किराए की राशि ब्याज सहित लौटाएं

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (तृतीय) में मंजरी अतरौलिया ने भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रपति मैदान शाखा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी का उनकी माता के साथ बैंक में संयुक्त खाता था। माता की मृत्यु के बाद उस खाते को परिवादी के एकल नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। परिवादी ने नामिनी होने के नाते अपनी माता के बैंक लॉकर को खोलना चाहा, लेकिन बैंक ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। दूसरी ओर उनके खाते से वार्षिक लॉकर शुल्क की कटौती जारी रखी। बैंक का तर्क था कि परिवादी लॉकर के लिए नामांकित नहीं है। उन्हें लॉकर न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही खोलने दिया जाएगा।

उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब परिवादी ने माता के निधन की सूचना बैंक को दे दी थी तो उनके बचत खाते से शुल्क काटना पूरी तरह गलत है। यह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने बैंक को आदेश दिया कि वह परिवादी के बचत खाते से वसूली गई राशि 9 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाए, साथ ही कानूनी खर्च और मानसिक संताप की एवज में 11,000 रुपए भी दें।

बैंकिंग व साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जमाकर्ता हो रहे जागरूक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं 'कट्स' जयपुर के सहयोग से अजमेर जिले के हिंगोनिया गांव में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी के.एन. वर्मा ने कहा है कि बैंकिंग फ्रॉड, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हम सभी को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बैंकिंग प्रक्रिया के अतंर्गत आपातकालीन वित्तीय सुविधा, आय की सुरक्षा व सुनिश्चितता, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक में अंतर, राशि हस्तांतरण विधियां व डिजिटल लेन-देन जैसी कई उपयोगी जानकारियां दी।

विकासोन्मुख संस्थान के सचिव राजेश मालाकार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी एवं 'कट्स' जयपुर के राजदीप पारीक ने संभागियों को जमाकर्ता शिक्षा से संबंधित योजनाओं एवं जमाकर्ता के अधिकारों के बारे में बताया। बैंक ऑफ इंडिया केकड़ी शाखा के प्रबंधक नरेंन्द्र चौधरी ने संभागियों को बैंक में खाता खोलने, विभिन्न जमा योजनाओं से होने वाले लाभों और जमाकर्ता के अधिकारों की जानकारी दी। वन स्टॉप सखी सेंटर की टीना शर्मा तथा दीपांशी ने फ्रॉड के बाद होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 50 संभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

रंगे हाथों पकड़ा तो बजाए ढोल

प्रदेश के पाली जिले की बाली तहसील के लाटाड़ा गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पटवारी विक्रम धीर को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ढोल बजा कर खुशी जताई।

ग्रामीणों के अनुसार पटवारी बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करता था। एसीबी के अनुसार पटवारी ने परिवादी की क्रय की गई भूमि के नामांतरण और विभाजन के लिए 11 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। पहले वह 5 हजार रुपए ले चुका था। इसके अलावा वह परिवादी की मां के नाम दर्ज भूमि के सीमांकन के लिए 2 हजार रुपए और पहले किए कार्यों की एवज में 6 हजार रुपए और मांग रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन के बाद जाल बिछाया और पटवारी विक्रम धीर को 8 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। यह खबर प्रदेश के गांवों के लिए प्रेरणा दायक है।

मानसून से पहले बांधों की 'हेल्थ चेक'

केंद्र सरकार डेम सेफ्टी एक्ट के तहत देशभर के 6000 से भी अधिक बांधों की पहली बार संयुक्त जांच करवा रही है। इसका उदेश्य बांधों की स्थिति, सुरक्षा और रखरखाव की जानकारी जुटाना है। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे बदहाल स्थिति वाले बांधों की पहचान हो सके।

राजस्थान में डेम सेफ्टी एक्ट के तहत प्रदेश में छोटे बड़े 315 बांधों की सेहत जांचने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि मानसून से पहले किसी भी खतरे या कमी को समय रहते दूर किया जा सके। जांच के दौरान बांधों की मजबूती, रखरखाव, मरम्मत, जलभराव क्षमता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बांधों के जल भराव क्षेत्रों में अतिक्रमण तो नहीं बढ़ गए हैं, जिससे पानी की आवक प्रभावित हो रही हो।

डिजीटल हेल्थ मिशन की जमीनी हकीकत

प्रदेश में डिजीटल हेल्थ मिशन की रफ्तार कागजों में तो तेज दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अभी भी करीब 60 फीसदी मरीज आभा आइडी से दूर है। आभा आइडी में मरीज का पूरा रिकॉर्ड एक जगह होता है। बार-बार रजिस्ट्रेशन से राहत मिलती है। किसी भी अस्पताल में इलाज का डेटा साझा हो सकता है।

ग्रामीण और छोटे शहरों में लोग आइडी तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। डिजिटल हेल्थ मिशन की बड़ी चुनौती तकनीकी और व्यावहारिक है। ओटीपी आधारित लॉग-इन प्रक्रिया कई मरीजों के लिए जटिल है और इससे उनको निजता का डर बना रहता है।

मिट्टी बचेगी तभी बचेगी खेती

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गांव रामसिया से राष्ट्रव्यापी स्तर पर 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया है। अभियान का खास मकसद किसानों को रासायनिक खेती से दूर कर केमिकल-मुक्त और जैविक खेती की ओर प्रेरित करना है।

उन्होंने कहा कि धरती की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए हर खेत का सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। धरती की उर्वरा शक्ति को बचाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए केंद्र सरकार इस अभियान के तहत स्वस्थ मिट्टी के जरिए किसानों को सशक्त बना रही है। मिट्टी बचेगी तभी खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। एक विशेष मोबाइल ऐप की मदद से मिट्टी की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि जमीन को कितने खाद की आवश्यकता है।

बजट चवन्नी खर्चा रुपया...

राजस्थान के जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री की खरीद को लेकर बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। नियमों में स्पष्ट 10 हजार रुपए की सीमा के बावजूद वार्डनों ने करोड़ों रुपए की खरीद कर डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच करीब 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए।

इस खर्च के लिए न तो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और न ही किसी स्तर पर जांच या सत्यापन हुआ। प्रदेश के 376 छात्रावासों में बड़े पैमाने पर यह खाद्य सामग्री खरीदी गई। गंभीर सवाल यह है कि यह खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई, इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। जब अलग अलग छात्रावासों के बिलों की जांच की गई तो उनमें भारी विसंगतियां निकली। सरकार ने बाद में पारदर्शिता के लिए टैंडर निकाले, लेकिन पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही फर्म सामने आई।

बाजरे की नई किस्म से बढ़ेगी पैदावार

केंद्र सरकार की 'श्री अन्न' (मिलेटस) को बढ़ावा देने की मुहिम के बीच जयपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरे की ऐसी हाइब्रिड किस्म विकसित की है, जो कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी अधिक उत्पादन देने के साथ सूखे और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है।

जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (रारी) ने इक्रीसैट के सहयोग से देश की पहली थ्री-वे हाइब्रिड बाजरा किस्म 'आरएचबी-273' विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस वर्ष जारी 184 उन्नत फसल किस्मों में इसे शामिल किया है। इस किस्म को देश के ए जोन के लिए स्वीकृति मिली है। इससे राजस्थान के साथ हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रदेश में पर्यटन को लगेंगे पंख

केंद्र सरकार के 'मेरा गांव मेरी धरोहर' प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 40 हजार में से 25 हजार से ज्यादा गांवों का डिजिटल डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस पहल से न केवल ग्रामीण पर्यटन को पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

डिजिटल प्रोफाइल में गांव की ऐतिहासिक विरासत, ग्रामीण पर्यटन, तीज-त्योहार, पारंपरिक शिल्प, खान-पान, पहनावा व गहने,

धार्मिक मान्यताएं, गांव के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख लोक कला जैसी बिंदुओं पर केंद्रित है। इससे अब विदेशी और घरेलू पर्यटक शहरों के साथ आस-पास के गांवों में दो-तीन दिन के भ्रमण की योजना भी बना सकेंगे। मंत्रालय का मानना है कि इस डिजिटल पहुंच से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बाजार में बेच दिया बच्चों का निवाला

सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील के गेहूं व चावल की सप्लाई में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सामान सप्लाई करने वाली फर्म ने ही 2426 क्विंटल गेहूं व चावल बाजार में बेच खाया। अब रसद विभाग व शिक्षा विभाग ने फर्म प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया है।

सीकर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिड डे मील में फूड प्रोडक्ट सप्लाई के लिए अगस्त 2024 से मार्च 2025 के लिए बिलाड़ा की मैसर्स भवानी इंडस्ट्रीज का टेंडर एक साल के लिए दिया गया था। इसी फर्म की ओर से फर्जीवाड़ा किया गया है।

वीबी-जी-राम-जी योजना लागू

केंद्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में बताया कि 1 जुलाई से सभी राज्यों में मनरेगा की जगह वीबी-जी-राम-जी योजना लागू हो जाएगी।

इस योजना के लिए कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि देश की करीब 2.80 लाख ग्राम पंचायतों को सीधे मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि ट्रांजिशन के दौरान एक भी मजदूर बेरोजगार न रहे और समय पर मजदूरी का भुगतान हो।

स्ट्रीट वेंडर्स बन रहे आत्मनिर्भर

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अब प्रदेश में फुटपाथ विक्रेताओं व रेहड़ी-ठेला लगाकर परिवार चलाने वाले लाखों गरीब व छोटे कारोबारियों को आत्म-निर्भर बना रही है। अब तक योजना के तहत तीन लाख परिवारों को 429 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

इससे इन कारोबारियों की आय में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो समय पर बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज की किस्त समय पर चुका रहे हैं। योजना में समय पर ऋण की किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485